प्रेस विज्ञप्ति

16.05.2025

यूके उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी को, जो पीएनबी के खिलाफ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का मुख्य साजिशकर्ता है, उसकी चौथी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए गुरुवार यानी 15/05/2025 को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और अभियोजन पक्ष (भारत सरकार) की जवाबी दलीलों, ईडी द्वारा लिखित निवेदनों (जिसमें शेल कंपनियों के जरिए आगम के यूके सहित बाह्य अधिकार क्षेत्रों में शोधन करने के धन-शोधन से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है) पर विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद और धोखाधड़ी की मात्रा (जिसका कुछ हिस्सा ईडी द्वारा पहले ही कुर्क/जब्त किया जा चुका है और पीड़ित बैंकों को वापस कर दिया गया है) को ध्यान में रखते हुए, यूके के उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज करते हुए नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने 19/03/2019 को भारतीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर यूके सरकार को किए गए गिरफ्तारी-अनुरोध के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसने 6 बार यूके वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट न्यायालय से और 3 बार यूके उच्च न्यायालय से जमानत पाने के कई प्रयास किए थे। हालांकि, प्रत्येक बार संबंधित यूके न्यायालय ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

हाल ही में, लंबा समय बीत जाने और स्वास्थ्य आदि के अन्य आधारों का हवाला देते हुए, नीरव मोदी ने 21/03/2025 को यूके उच्च न्यायालय के न्यायधीश किंग्स बेंच डिवीजन के समक्ष अपनी चौथी जमानत याचिका दायर की, जिसमें यूके के जिला न्यायाधीश ज़ानी के दिनांक 07/0/2024 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दायर आवेदन में कार्यवाही के हिस्से के रूप में, जमानत आवेदन पर व्यापक रूप से सुनवाई की गई, जिसमें भारत सरकार (सीपीएस वकील टीम और ईडी और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के माध्यम से) ने नीरव मोदी को जमानत देने का कड़ा विरोध किया, जिससे भारत सरकार के लिए अनुकूल परिणाम सामने आया।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 6498.20 करोड़ रुपये (यूएसडी 1.015 बिलियन) की धोखाधड़ी के लिए सीबीआई, बीएस और एफसी शाखा, मुंबई द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर ईडी मुंबई द्वारा 14/02/2018 को नीरव मोदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया गया था। पीएमएलए के तहत की गई जांच के हिस्से के रूप में, ईडी भारत और विदेशों में 2626.62 करोड़ रुपये की संपत्ति/परिसंपत्तियों का पता लगाने में सक्षम रही है और इस प्रकार, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ऐसी पहचान की गई संपत्तियों को कुर्क किया है। आगे, नीरव मोदी और 35 अन्य आरोपी व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई के समक्ष 24/05/2018 को अभियोजन शिकायत और 28/02/2019 को पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई हैं। इसके साथ ही, गिरफ्तार भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही लंदन, यूके में अंतिम चरण में है।

साथ ही साथ, इस मामले में, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायालय, मुंबई द्वारा नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के बाद नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 692.90 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा, कुल कुर्क/जब्त संपत्तियों में से, 1052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति पीड़ित बैंकों यानी पीएनबी संघ (कंसोर्टियम) बैंकों को सफलतापूर्वक वापस कर दी गई है (अब तक)।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।